SHRI N. R. MUNISWAMY: Sir, there is a Clause and it is Clause 5.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI (Rajasthan): Sir, there is no answer from the Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister says that she does not have the information at the present moment.

SHRI A. D. MANI: Sir, it is a very relevant question.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, I have already mentioned that it is the Government employees. I have mentioned in my earlier speech and in reply to some other question that those who are already getting it, they are entitled in future also, that is. those who are already entitled will be entitled in the future also . . . *(Interrwptions.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Whenever the notification is issued, I think, it will be made known to the House.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Yes, Sir.

SHRI N. R. MUNISWAMY: Sir, we can know it if it is clarified.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: It should be clarified.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister has said that she does not have the information at the present moment. Perhaps the category of persons would be decided also later.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: By notification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If the hon. Minister gets it in the meantime, she may try to give it in the after-noon. Perhaps there is no final decision on the categories. There may not be any information available with the Government also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till quarter past two.

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at quarter past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

STATUTORY RESOLUTION DISAPPROVING THE STAMP AND EXCISE DUTIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1971 (NO. 17 OF 1971), PROMULGATED BY THE PRESIDENT ON THE 22ND OCTOBER 1971

THE STAMP AND EXCISE DUTIES (AMENDMENT) BILL, 1971

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान): उपसभापति जी, मैं एक संकल्प उपस्थित कर रहा हूं कि—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अक्तूबर, 1971 को प्रख्यापित स्टाम्प और उत्पाद-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 16) का निरनुमोदन करती है।"

जिन कारणों से मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं, संक्षिप्त रूप में उसकी कुछ बातें मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित करूंगा। यह अध्यादेश 22 अक्तूबर को जारी किया गया था और उसमें स्टाम्प और उत्पादन-शुल्क की वृद्धि 15 नवम्बर, 1971 से लागू किए जाने की बात थी। राष्ट्रपति के द्वारा संसद् के दोनों सदनों को आहूत करने की सूचना 22 अक्तूबर के पूर्व जारी की जा चुकी थी अर्थात् अध्यादेश को जारी करते समय सरकार को इस बात की जानकारी थी कि जिस दिन इन अध्यादेशों को कार्यान्वित होना है उस दिन सदन् बैठ चुका होगा और एक प्रकार से सदन् जिस दिन बैठा हुआ है उस दिन से किसी अध्यादेश का लागू होना, यह जनतांत्रिक परिपाटी के लिए कभी भी उचित नहीं माना जा सकता और इस कारण मेरा यह आरोप है कि सरकार ने एक ऐसे अध्यादेश को जारी करके जो सदन् के बैठने के दिन से लागू होने वाला था, सदन् का अपमान किया है, संविधान के अंतर्गत आर्डिनेन्स जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग किया है। तो मैं चाहूंगा

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

कि सरकार इस सबंध में कम से कम भविष्य के लिए एक निश्चित नीति बनाए कि जो अधिकार संविधान के द्वारा उसे मिला है, उस अधिकार की मार्फत नए टैक्स लगाने का विचार किया जाए और सदन् की अवमानना करने का प्रयत्न इस प्रकार के किसी भी अध्यादेश को जारी करके न किया जाए ।

अध्यादेश को जारी करते समय यह आधार लिया गया कि परिस्थिति विशेष प्रकार की है । आज के संदर्भ में यह बात सही है कि परिस्थिति विशेष प्रकार की है । परन्तु इस बात को भी कि परिस्थिति इस स्थिति तक पहुंच क्यों गई, इस अवस्था तक क्यों पहुंची, हम आंखों से ओझल नहीं कर सकते ।

इस सदन् ने भी बंगला देश के प्रति सहानुभूति व सहायता के लिये सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया था । उस वक्त सरकारी पक्ष को छोड़ कर सभी पक्षों ने बंगला देश की सरकार को तुरन्त मान्यता देने का आग्रह किया था । सरकारी पक्ष का यह आग्रह था कि मान्यता देने के सवाल को सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिये और वह किसी उपयुक्त समय में बंगला देश की सरकार को मान्यता दे देगी । सच्चाई यह है कि आज तक वह मान्यता नहीं दी गई और अगर बंगला देश के कारण परिस्थितियां कुछ विशेष प्रकार की जटिल बनी हुई हैं, तो इसमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बात की है कि जो प्रश्न सरकार ने अपने फैसले के लिए रख लिया था उस पर फैसला क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं कदम बढ़ाया गया और मान्यता क्यों नहीं दी गई । मान्यता देने के बाद जो एक स्वाभाविक पग था कि बंगला देश सरकार को सैनिक सहायता देकर बंगला देश में होने वाले अत्याचारों और उन अत्याचारों के परिणामस्वरूप भारत में आने वाले विस्थापित बन्धुओं का आना रुकना था । इस चीज के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो सफल अभियान चलाया जा सकता था वह सम्भव नहीं हो सका और यही वजह है कि इन विस्थापितों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गई है और अब भी प्रतिदिन 10 हजार से लेकर 20 हजार तक/परिस्थितियां नर्म और अधिक कठोर होने के अनुपात में वह संख्या प्रति दिन घटती और बढ़ती जा रही है । इसलिए बंगला देश के विस्थापितों के कारण बढ़ा हुआ खर्च हमारे ऊपर आया है । तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है या सरकारी पक्ष पर है जिसने इस बात को हमेशा दोहराया कि मान्यता के सवाल को सरकार पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये । उसके ऊपर यह सीधी जिम्मेदारी आती है कि इन 6–8 महीनों में इस प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय क्यों नहीं किया गया और मान्यता के सवाल पर फैसला स्थगित करना यह किसी भी प्रकार से जस्टीफाइड नहीं माना जा सकता है । कोई भी कारण आज तक सरकार या सरकारी पक्ष नहीं दे पाया है कि अगर यह मान्यता का सवाल आज से पहिले यानी अप्रैल में या अप्रैल के बाद जल्द से जल्द तय कर लिया गया होता तो आज देश को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, उससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता या फिर परिस्थितियां इससे ज्यादा विषम बनतीं और देश को जो आज बोझा उठाना पड़ रहा है, उससे ज्यादा बोझा उठाना पड़ता । किस कसौटी पर बंगला देश की सरकार को मान्यता देने के प्रश्न को अनिर्णीत रखा गया और कौनसी परिस्थितियां इस विषम स्थिति के लिए कारणभूत हुई ? इसमें जितना समय बढ़ेगा तथा लगेगा उससे हमारे लिए समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी ।

कल इसी तरह के बिल के सम्बन्ध में जब चर्चा हो रही थी तो सरकार की तरफ से कहा गया कि बंगला देश के विस्थापितों में इस फाइनेंसियल ईयर में (1971-72) जो खर्चा आंका गया है और वित्त मंत्री जी ने भी बाहर किसी इन्टरनेशनल कांफ्रेंस में जिस का उल्लेख किया था वह करीब 525 करोड़ के लगभग था । जिस समय श्री चव्हाण साहब ने यह आंकड़े बतलाये थे उस समय उन्होंने विस्थापितों की संख्या का क्या अनुमान लगाया ? क्योंकि विस्थापितों की

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती ही चली जा रही है। इसके बारे में सरकार स्थिति को स्पष्ट करेगी। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि उस समय से विस्थापितों की संख्या अधिक बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है और वर्ष के अंत तक यह संख्या और भी बढ़ती ही चली जायेगी। 525 करोड़ रुपये की जो राशि आंकी गई है, उसमें कितने और अंक जुड़ जायेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

बंगला देश के विस्थापितों के नाम पर विभिन्न प्रकार के कर लगाये गये हैं और कुल वर्ष के हिसाब से उनका मूल्यांकन 70 करोड़ रुपये के लगभग था। आधे वर्ष के लिये 30–35 करोड़ रुपये इसमें से और आ सकेंगे। बजट में इस मद के लिए 60 करोड़ रुपये रखे गये थे, पूरक बजट में 200 करोड़ रुपये रखे गये हैं और टैक्स प्रपोजल्स के आधार पर 30–35 करोड़ रुपया जोड़ा जाय तो कुल राशि 300 करोड़ रुपये से कम होती है। जबकि इस वर्ष में ही हमको सवा 5 सौ करोड़ से अधिक, साढ़े पांच और छः करोड़ तक इसमें कुल खर्चा करना पड़ेगा अर्थात् इन आर्डिनेसेज का सहारा लेने के बाद और उन के बाद जो बिल पास किये गये हैं, उनका सहारा लेने के बाद भी बंगला देश के विस्थापितों पर होने वाला कुल खर्च जो है उसे कवर नहीं किया गया है। उस में गैप छोड़ा गया है। पहले जब बजट पेश हुआ था तो इतने भारी टैक्स लगा कर भी एक गैप छोड़ा गया था। तो वह गैप और यह गैप मिला कर, कीमतों की बढ़ोत्तरी के कारण और देश में मुद्रास्फीति की परिस्थितियों के कारण यह आशंका है कि इन टैक्सों के बावजूद हमारा बजटरी गैप या इस वर्ष का डेफ़िसिट फाइनेंसिंग कहीं 900 करोड़ के करीब जा कर पहुंचेगा, तो मैं इसलिये इसका विरोध कर रहा हूं कि फिर इतने बड़े गैप में यह 70 करोड़ का टैक्स लगाना, इस के पीछे कौन सा तर्क है। हां, यह बात जरूर है कि बंगला देश के विस्थापितों के प्रति देश में सहानुभूति है। बंगला देश की समस्याओं को हल करने के लिए सारा देश एक मत है। बंगला देश की आजादी के लिए यह देश अगर खुद अपने घर में भी कठिनाई आये, युद्ध परिस्थितियां आयें तो भी इस देश ने उसके लिये अपनी सहमति और समर्थन सरकार को दिया है और उसे आश्वस्त किया है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को इस भावना के प्रति खिलवाड़ किया जाय।

इसलिए मझे इस पर आपत्ति है कि अगर देश बंगला देश के सवाल पर सब प्रकार के कष्ट झेलने के लिए तयार है, युद्ध भी सिर आये तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं तो फिर बंगला देश के विस्थापितों के नाम पर एक नया टैक्स लगाना देश की इस भावना के साथ मजाक करना या उसका दुरुपयोग करना मात्र है। बंगला देश के खर्च का पूरा हिसाब भी इसमें नहीं आता और अंततोगत्वा बंगला देश के विस्थापितों पर होने वाला खर्च जनरल रेवेन्यू में से या जनरल डेफिसिट में से जायगा। बंगला देश के नाम पर यह 70 करोड़ रुपया लेकर देश की बंगला देश के प्रति जो सहानुभूति है, जो भावना है उस का एक्सप्लाएटेशन किया जा रहा है। यह उन के साथ अनुकूल नहीं बैठता। अच्छा होता कि सरकार बंगला देश के नाम पर टैक्स लगाने के बजाये बंगला देश के संभावित खर्चे को भी जनरल एक्सचेकर का खर्चा बना कर सारे देश के स्वाभाविक खर्च का एक भाग बनाती। ऐसा होने पर बंगला देश की अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर जो देश में विभिन्न प्रकार की इकोनामीज़ करने की बातें की जा रहीं है, उनकी सीरियसनैस और बढ़ जाती और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर सरकार का हो रहा है, जो ओस्टेंटेशस एक्सपेंडिचर को कम करने की बातें को जा रही हैं वह बंगला देश के विस्थापितों के इस खर्चे को मद्दे नजर रख कर उन खर्चों को कम करने की बात कुछ ज्यादा वजनदार बनती। सरकार को भी इस प्रकार की कमियां कहां-कहां की जा रही है, कितनी मात्रा में की जा रही हैं या की गयी हैं और उनसे नेट सेविंग कितनी होगी

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

इस बात को भी सामने रख कर बंगला देश के विस्थापितों के बढ़े हुए खर्च के संदर्भ में अपने टोटल बजट में उतनी कटौती कर के इस समस्या के समाधान के लिये आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता ।

पीपुल्स पार्टिसिपेशन की बात कही जा रही है । तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन केवल 70 करोड़ में से प्रदर्शित नहीं होगा । इस पीपुल्स पार्टिसिपेशन को हम इस तरह से नहीं ले सकते हैं । बंगला देश के कारण पड़ने वाले कांसीक्वेंशियल परिणामों में पता नहीं कितने हजार करोड़ तक पीपुल्स पार्टिसिपेशन की आवश्यकता पड़ेगी । यह संकट जिस रूप में देश में बना हुआ है—इससे भागने का कोई कारण नहीं, इससे डरने का कोई कारण नहीं—उसके कारण पीपुल्स पार्टिसिपेशन की आवश्कतायें न केवल आर्थिक क्षेत्र में, कुल मिला कर सरकार के जनरल बजट में ही नहीं, बढ़े हुए बजट में ही नहीं, उसके कारण दूसरे मामलों में भी, सिविल डिफेंस में और बढ़िया तरह से भी यहां तक कि नागरिकों के रात-दिन के क्षेत्र में भी जो पीपुल्स पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है, उस पीपुल्स पार्टिसिपेशन के बिना तो सरकार पंगु हो जावेगी । उस पीपुल्स पार्टिसिपेशन का केवल 70 करोड़ के नाम पर आह्वान करना यह पीपुल्स पार्टिसिपेशन को डैनीग्रेड करने के समान है, यह पीपुल्स पार्टिसिपेशन की भावना के प्रति एक मजाक है और इसलिये मेरा यह कहना कि यह टैक्स प्रोपोजल्स आर्डिनेंस की मार्फत या टैक्स प्रोपोजल्स को बंगला देश के रिफ्यूजीज की सहायता के लिये एक अलग आइटम बना कर वसूल करने की धारणा, कुल मिला कर देश की जिस गम्भीर परिस्थिति का उल्लेख किया जा रहा है और जिस गम्भीर परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिये किया जा रहा है, उन दोनों का इसमें मेल नहीं खाता । अच्छा होता कि सरकार इस प्रकार के आर्डिनेंसेज या इस प्रकार के बिल के द्वारा विस्थापितों के नाम पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव से गुरेज करती । यह बात उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है न देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल है । यह खर्चा सारे देश का खर्चा है, यह खर्चा सारे सरकारी खजाने का खर्चा है उसी का भाग बने । लोग क्योंकि इस प्रकार के एडिट टैक्सेशन में करों का बंगला देश के साथ सहानुभूति होने के कारण विरोध करने के लिये तत्पर नहीं होंगे, इसी लिये इस नाम पर इस तरह से इसको टैक्स का रुप देना, यह मैंने जैसा कि निवेदन किया लोगों की भावनाओं के प्रति न्याय नहीं है, यह उनकी देश भक्ति पर शक करना है । बंगला देश की आड़ ले कर उनसे टैक्स वसूल करने का यह जो तरीका है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं । यह देश के लोगों के प्रति अन्याय है । देश के राष्ट्रीय प्रयत्नों में लोगों को स्वाभाविक रूप से जुटाने के बजाय केवल उनकी किसी नाड़ी, कमजोर नाड़ी को हाथ लगा कर उसको रजामन्द करने के समान है । यह प्रवृत्ति निन्दनीय प्रवृत्ति है, देश के प्रति एक अन्याय करने वाली प्रवृत्ति है । इस प्रकार का सहारा नहीं लेना चाहिये था ।

श्री नेकी राम (हरियाणा) : भंडारी जी, आपको नमक-मिर्च खूब लगाना आता है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपका घाव तो ऐसा है कि नमक की बोरियां डाल दें तब भी असर नहीं होगा ।

श्रीमन्, इस आर्डिनेंस में जब अखबारों पर दो पैसा एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात कही गई तो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि नोटिफिकेशन के जरिये से बाद में पन्द्रह हजार तक के सर्कुलेशन के अखबारों को छूट देने का इसमें प्रावधान किया गया था । आर्डिनेंस में इसका समावेश नहीं हुआ यह बात समझ में आ सकती है । लेकिन जब बिल आज पेश किया जा रहा है तो इस बिल में भी इन छोटे समाचार पत्रों को राहत रहेगी इस प्रोविजो या एक्जेम्प्टिंग क्लाज का समावेश नहीं हुआ है । नोटिफिकेशंस की बात आर्डिनेंस के अन्तर्गत हो, एक लैकूना को पूरा करने के लिये ऐसा किया गया हो यह बात समझ में आ सकती है । लेकिन आज जबकि बिल पेश किया जा रहा है और

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

सरकार अपनी बात के प्रति ईमानदार है, सरकार अगर वास्तव में छोटे समाचार पत्रों को सब-एडीशनल ड्यूटी से एग्जेम्पट करना चाहती है तो फिर इस बिल में जो सरकार सदन के सामने विचार के लिये रखना चाहती है उस बिल में इसका उल्लेख न होना उस नोटीफिकेशन की ईमानदारी पर शक पैदा करता है। क्योंकि अगर यह बात ध्यान में आ गई और सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि छोटे समाचार पत्रों को इसमें से माफ किया जायगा तो इस बिल में ही, इस बिल के अन्दर ही, जहां दो पैसा लगाने का प्रस्ताव है, वहां इसी बिल में इस बात का एक संशोधन, एक अपवाद होना चाहिये था कि 15,000 तक की सर्कुलेशन वाले अखबार का जो पत्र या पत्रिका साधारणतया कीमत पर बेचे नहीं जाते, मुफ्त में दिए जाते हैं, कालेज की मैगजीन्स हैं या और दूसरे प्रकार के पत्र हैं, उन पर यह ड्यूटी लागू नहीं होगी। यह स्पष्ट प्रावधान इस बिल में होना चाहिए था। मुझे खेद है कि जब सरकार ने इस बात का उल्लेख बिल में नहीं किया है तो नोटिफिकेशन की ज्यादा कीमत नहीं। नोटिफिकेशन की कोई कांस्टीट्यूशनल और पार्लियामेन्टरी सेंक्शन नहीं है और उस नोटिफिकेशन से पीछे हटना सरकार के लिए कभी भी संभव हो जाएगा। एक बार बिल में फिर से इस प्रकार का अधिकार मिल जाने के बाद कि जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं किया गया है। इसलिए सरकार के उस नोटिफिकेशन को इस बिल को देखने के बाद महत्व देना और उसमें छोटे अखबारों को इस ड्यूटी से मुक्त करने का जो विचार किया है, अगर सरकार इसके प्रति कायम रहना चाहती है तो इस बिल में ही सरकार की तरफ से संशोधन, इस एग्जेम्शन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए था। (*Time bell rings*) में समाप्त कर रहा हूं।

इसके साथ-साथ जो स्टेम्प्स पर लिखा हुआ है वह रिफ्यूजी रिलीफ लिखा हुआ है। अब यह बात आपने एक्सप्लेनेशन में जरूर कही है कि यह बंगला देश के रिफ्यूजीज के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अन्दर बरती गई नीतियों और भारत में अनेक क्षेत्रों से आने वाले रिफ्यूजीज की वह अबाध शृंखला 1947 से 1971 तक चली आ रही है। वह रिफ्यूजी शब्द जिस उद्देश्य को लेकर आज यह आर्डिनेन्स जारी हुआ और यह बिल आया उसमें उसकी पूर्ति नहीं करता। आवश्यकता है कि जिन स्टाम्प्स पर यह शरणार्थी सहायता शब्द लिखा हुआ है। तो उन स्टाम्प्स पर जो अभी भी छप रहे हैं, जो पूरे नहीं छपे, अगर सरकार फैसला करे तो आगे से उस पर "बंगला देश विस्थापित सहायता," इतना पूरा लिखा जाए तब तो इस आर्डिनेंस की जो भावना है, जो बंगला देश के नाम से टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, उसमें जैसा आपने कहा कि "पीपुल्स पार्टिसिपेशन" यह उनके दिमाग में रहे कि यह किस मतलब के लिए है, उस भावना की पूर्ति होगी नहीं तो वह मतलब पूरा स्पष्ट नहीं होता। तो सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे कि आगे से छपने वाले स्टाम्प्स पर बंगला देश विस्थापित सहायता, इन शब्दों का प्रयोग होगा। स्टाम्प्स पर इतनी गुंजायश है। क्योंकि जिस तरीके के अक्षर छापे गए हैं वे किसी भी प्रकार से, उन स्टाम्प्स पर ड्यूटी की तरह से जो चीजें हैं, छापी जा सकती हैं। यह स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख करना चाहिए।

यह तो बिल की बात रही। कम से कम आर्डिनेन्स के द्वारा यह चीज नहीं आनी चाहिए थी। आर्डिनेन्स इसके लिए बिलकुल आवश्यक नहीं था, यह मेरा निवेदन है। आर्डिनेन्स को लागू करने के लिए जो एक कारण दिया है कि कुछ फार्मेलिटीज हमको पूरी करनी थीं, 15 नवम्बर के पहले, तो मैं मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी फार्मेलिटीज थीं स्पष्ट रूप से गिनाया जाए कि अगर यह आर्डिनेन्स न निकाला गया होता तो 15 तारीख तक उन फार्मेलिटीज को पूरा करना संभव नहीं था या डिपार्टमेन्ट्ली उस पर एक बार था, एक रेस्ट्रिक्शन था, इस मामले में सरकार आगे नहीं बढ़ सकती थी, वह चीज यहां पर डीटेल में बताने की आवश्यकता होगी। केवल यह कह कर कि फार्मेलिटीज की

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

जरूरत नहीं थी इसलिए यह आर्डिनेन्स जारी किए बिना वे फार्मेलिटीज पूरी नहीं की जा सकती थीं, (क्योंकि कम से कम इस अर्से में कोई वसूली तो नहीं हुई) तो ऐसी कौन सी फार्मेलिटीज हैं, जिनको 15 नवम्बर के पहले, बिना आर्डिनेन्स जारी किए, सरकार नहीं कर सकती थी । कई बजट प्रस्तावों में भी इस प्रकार की चीजें रहती हैं, बजट के वह प्रपोजल, जिस दिन बजट का भाषण होता है उस दिन से लागू होते हैं । बजट के फार्मल एनाउन्समेंट के पहले आवश्यक फार्मेलिटीज पूरी कर दी जाती हैं, उसके लिए कोई विशेष अध्यादेश की आवश्यकता नहीं रहती तो बजट प्रपोजल्स तत्काल लागू करते समय जो फार्मेलिटीज पहले पूरी कर दी जाती हैं, इसी प्रकार इन ड्यूटीज को लागू करते समय कौन सी फार्मलिटीज थीं जो लागू नहीं की जा सकती थीं ? इस दृष्टि से इस अध्यादेश की क्या आवश्यकता हुई, इसका स्पष्टीकरण किए बिना कोई दूसरा तर्क नहीं रहता, जिसकी वजह से इस प्रपोजल्स को अध्यादेश द्वारा जारी करने की आवश्यकता थी ।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाए ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE/ **वित्त मंत्रालय में उप मंत्री** (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): Sir, I beg to move— "That the Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899. the Central Excises and Salt Act, 1944 and the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the hon. Members are aware I that the Government had taken certain steps to raise additional resources to meet the expenditure for relief of Bangla Desh refugees after discussing the matter with the Governors and the Chief Ministers of States at a meeting held in New Delhi on the 12th October. 1971.

The Stamp and Excise Duties i (Amendment) Ordinance, 1971 (16 of I 1971) was promulgated by the President on the 22nd October, 1971, with a view to impose the following duties with effect from the 15th November, 1971:

(a) an additional duty at a fiat rate of 10 paise per instrument on Biil of Exchange, Bill of Lading, Debenture, Letter of Credit, Policy of Insurance, Promissory Note, Proxy, Receipt and Transfer of Shares falling under Entry 91 of the Union List. Under Article 268(2) of the Constitution, the proceeds of this additional stamp duty would accrue to the States. Since the States would make available to the Centre the additional revenues so raised, the additional duty is collected by means of special adhesive stamps t ing the inscription. "Refugee Relief". This facilitates accounting and subsequent transfer of the proceeds by the States to the Centre. The additional stamp duty is likely to yield a revenue of about five crores of rupees in a full year and Rs. 1.9 crores in the current financial year.

(b) an excise duty at the rate of two paise per copy on newspapers and other printed periodicals. By notifications issued under the Central Excise Rules, the following categories are exempted from this duty: —

(i) Newspapers and periodicals whose average circulation does not exceed 15.000 copies per publishing day; and

(ii) Newspapers and periodicals not ordinarily intended for sale.

Like other excisable commodities the facility of export under claim for rebate or alternatively under bond has also been extended to this item.

To ensure smooth functioning of this excise levy, certain procedural relaxations like the extension of Self Removal Procedure, simplification of licensing formalities, requirement of gate passes and acceDtance of the licensees' records etc. have also been made.

The above duty on newspapers and other minted periodicals was expected to yield a revenue of

Rs. 7 crores in a full year and of about Rs. 2.6 crores in the current financial year. However, the exemptions from duty referred to earlier are likely to reduce the estimated annual collections by aDout Rs. 1.75 crores.

Under the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, the proceeds of Union duties of excise are distributed amongst the States on the basis of the distribution formula laid down in that Act. Since the excise duty on newspapers has been levied for meeting the expenditure on relief of Bangla Desh refugees, it has been provided by amendment of the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, that the proceeds of this duty shall not be distributed to the States and will accrue to the Centre.

Sir, it became necessary to impose these levies through an Ordinance for the following' reasons: —

(i) Parliament was not then in session:

(ii) Action had to be taken immediately to raise maximum resources, as delay would have impeded our efforts in this direction.

(iii) Steps were to be taken to make the special adhesive stamps available to the general public. A large number of stamps had to be printed at the Security Press. Further, steps were also to be taken to make these stamps available in all the treasuries etc. throughout India.

(iv) For the purposes of imposition of excise duty on newspapers and other printed periodicals, it was necessary *to* initiate licensing formalities and to make the prospective licensees familiar with the excise procedure including the formalities under the Self Removal Procedure.

(v) It was also necessary to make all other administrative arrangements for the collection of the duties from the appointed date.

(vi) The date of effect of levies had to be kept as 15th November, 1971. as the above preparatory steps were required to be taken to avoid inconvenience to the public. Sir, I commend the present Bill,

as passed by the Lok Sabha, which seeks to replace the above Ordinance for unanimous acceptance by the House. Hon. Members will agree with me that the objective underlying the Bill is for a laudable purpose.

Sir, I move.

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanyal.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, before my friend, Mr. Sanyal, speaks, may I seek your permission to say a word or two? Mr. 'Bhandari, while opposing this sort of levy, has put forward certain points of view. We thought that when the Finance Minister was making her speech she would reply to them.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She was only moving the motion for the consideration of the Bill. When she replies at the end, perhaps she will refer to all the points raised.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): It is very difficult to anticipate what Mr. Bhandari was going' to say.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, it is a very unfortunte position in which we are placed today. The newspapers are the Fourth Estate and the people who read them are the Third Estate in a democracy. There is confrontation between the two valuable Estate of democracy. When the question of levy comes and a choice has to be made between the two, the choice is clear. After all, the newspapers earn and the newspaper readers only learn, if it is a question of putting a lew between earnings and learning, I think, the answer is clear. Those- who earn should bear the burden of the levy and those who learn should not be visited with this levy.

SHRT MAHAVIR TYAGI (Uttar sh): What about tuition fees?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: We are getting tuition fee without learning. We are learning and earning. That makes some difference. After all. who reads the newspaper— If you go early morning tc

[Shri Sasankasekhar Sanyal.]

the street corner, you will find many people. Hawkers, ordinary labourers, even sweepers, cobblers, teastall-holders all rush to the street corner in order to get hold of newspapers. Some of them read and some others read out to others. Why? They want to know how things are going on in the world. Particularly today they want to know how things are going on about Bangla Desh over there and the impact of Bangla Desh over here in our State, Here for some time, when the newspapers suddenly raised the prices, along with the levy, the people who wanted to know everything and had a clear idea were put to confusion and to wide speculation. This was the sort of thing which immediately called for some drastic action from the Government. I do not know why the maintenance of internal security was not considered at that time and the Government did not show the red eye, so that the earning machines of newspapers would have come to their senses forthwith.

You are putting this levy. But before that there was also the extra price. There has been a revision there. What I submit is. what has happened to the extra earning that has been made by the newspapers in the mean-time[9] Some newspapers sell only with the extra levy. But some newspapers in Calcutta have sold with 2 paise plus six paise extra. Some other newspapers also have suddenly gone up to as much as eight paise—2 paise plus six paise. Have thev been asked to eive it in favour of Bangla Desh? Are they losing? If they did not lose at that time, why did you not collect that extra in the name of Bangla Desh? This 2 paise levy also should not be the burden of the newspaper readers. Unemployed young men read the newspapers. They read the 'Wanted' columns. We cannot give them employment or employment insurance. But we force them to give two paise extra for seeing whether any appointment is anywhere available. The agriculturists read the newspapers because they want to know the price conditions, they want to know the prospects of the price of agricultural products. Why do you drive them into this predicament? Therefore, I plead with the Government. After all, on this issue there is no difference of opinion, and the Bangla Desh issue must be made and maintained popular. If the Bangla Desh issue is used for such purposes, then there is no end to all this and the whole Bangla Desh issue will become unpopular. Therefore, this excise should not fall upon the reader.

Sir, you know that excise has got its notional meaning also. It is like liquor and *ganja.* And they want to smoke *ganja* from the hands of ths poor readers. That is very unfortunate.

Then there is another matter. Newspapers are public utility services, they are essential services. They have been earning not only through selling newsprint in the black market, but also by selling newspaper at a higher rate to the readers, and they are earning profits through advertisements. They get big Government advertisements. If any Minister could not speak in good language, they put it in good language and boost the Minister. And the advertisements that they get from the Government are very lucrative.

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : आपकी गालियां भी छापते हैं ।

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: ^ ?rrf ?JT cfr f| ^ TTT, ^q-p-r sRTr SjrfqrrriTr,. I do not have teeth. My face cannot be painted properly. You are always enamoured of those who have got good appearance. But on this side there is no good appearance.

Sir, I was saying that the newspaper people get so many advertisements from the big commercial concerns and from the Government. Let them discard a particle of that profit in favour of Bangla Desh. It wil] not be harmful to them. In fact it will be a healthy trend. It will also put the newspapers into a position of glory which thev want to enjoy. But they have well become addicted to the policy of profit Only if they sacrifice something, they will induce some respect among

the readers, so far as the big industrial combines running the newspapers are concerned. On the Sunday issues this six paise extra is to be paid. But in the Sunday issues of the big papers of Delhi, two-thirds or three-fourths of the space is occupied by the advertisements.

I read my Ananda Bazar Patrika and Jugantar coming every evening from Bengal. Very much more than half their space is occupied with advertisements and we are left with scanty things to read. These advertisements give them so much profit. Why should they increase the price at all? Why should these daily napers increase the price of Sunday issues? After all, the advertisement takes bulk of the space, so manv pages extra. It is a bilateral deal between the business side of the newspapers and the government and other parties who put insertions by way of advertisements. If this is the bigamy between the two, why should the third party, the reader, who is neither of the bride's side nor of the bridegroom's side, be compelled to pay more? It is neither arithmetic nor logic. Therefore, I would submit. Sir. that you tax these newspapers. You appoint a committee of enquiry to see how far they are making profits and then you might go in for super-tax upon them. This will also open a window *to see* how much newsprint goes into the black market. They show inflated figures Thev get more from the newspapers. They have got their satellites, small napers. They feed them at thp black market rate and they make their humble profits. Therefore, the nrudent course for the hon'ble Minister would have been—it is still nossible—to levy two paise on napers with a circulation of 50,000. and above, and for papers between 20,000—50.000 make it one paise and make it nil for papers with lesser circulation. That will answer thp needs of the moment. This wiH also do some sort of justice between a paper and a paper becaus", after all it is the extra income which has to be taxed first, it is tbe substantia] income which his tn be ts--ed first T am sorrv to c">w that "n_{0r}>ip who do not have anv extra income have to J(N)8R8S—9 be settled with extra levies. This is not natural justice. Therefore, I plead that natural justice ought te weigh with the Government.

In this connection, Sir, may have a very uncomfortable matter raised here? I hope my friend, Mr. Yajee, will not jump up.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) : He does not jump up. He only shouts.

SHRI SASANKASEKHAR SAN-YAL: Sometimes he jumps at me because we were shoulder to shoulder. I say this because I had been to some of these camps on the borders. I live in the Nadia-Murshida-bad area. Although I cannot visit these places very frequently on account of growing age, still I have gone there.

AN HON'BLE MEMBER: You are young.

SHRI SASANKASEKHAR SAN-YAL: Youth is also growing. There should be a Parliamentary Sub-Committee in order Io investigate and supervise how the money, which is collected in the name of Bangla Desh, is being spent in the camps.

SHRI A. D. MANI: Very good point.

SHRI SASANKASEKHAR SAN-YAL: Although I belong to a particular party, still I do not grudge a good thing being done by any other party. I have gone there and I have seen that local people who have served the Bangla Desh refugees when they came, when there was no machinery, they do not get anything now.

SHRI PITAMBER DAS: I want to know whether he wants the committee for purposes of appreciating the performance or for criticising the performance.

SHRI SASANKASEKHAR SAN-YAL: For assessing the performance.

STTRI SHEEL BHADRA YAJEE: For creating confusion also.

SHRl SASANKASEKHAR SAN-YAL:I have seen the Sharnarthisare under the organisation of onlyone party. Even those who do notI belong to that party and who are.

[Shri Sasankasekhar Sanyal] residents of a place 20—40 miles away, they are inducted. And halt of the things available for the Sharanarthis goes to these people. Now they are setting[1] up volunteer organisations as a machinery for the election when it comes there. Incidental blackmarketing, incidental corruption, and incidental nepotism are rampant there. 3 P.M.

I have some good friends there. They belong to other parties. I have some friends who belong to the Congress (R). They do not like this sort of things there. But then the ruling parly has made it a point to induct only those persons who will stand by them in the elections and exclude these who will never stand by them in the elections. (Interruptions! I have given my personal experience. I am prepared . . . (Interruptions) I car prove it to the hilt . . .

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : Yon can prove anything because you are a vakil.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : एक कटु सत्य का उल्लेख कर रहे हैं

(Interruptions)

SHRI MAHAVIR TYAGI: If there is fny truth in these allegations, then an investigation is required.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: If there is no truth in the allegations, I am prepared to resign my seat in Parliament. Come along, ace ?pt this challenge. If relief sup-plies come to the *sharanarthis,* half the things go to the blackmarketeers of the Congress Party and the re-ma ning half goes to the *sharanar-thi*:. Some of them is sold to the Cor gress volunteers and these Cong-res; volunteers . . .

IHE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIA-MF NTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT/ ujanusm'AJ: Sir, there i ™ no truth inthat charge.

(Interruptions) SHRI MAHAVIR TYAGI: Let all facts come t ef ore the House.

SHRI DEV DATT PURI (Haryana): Sir, I protest vehemently against this wild allegation. I ask him to make this statement outside the House.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Yes, we have been making it outside the House also. We have deliberately not tried to expose you. If you insist, we will prove what is going on in the refugee camps.

SHRI DEV DATT PURI: We are not dependent on your mercies. I ask you to make this statement outside the House.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: We have made it outside also. If you are deaf, we cannot help you.

श्री हिरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : आउटसाइड को क्या जरूरत है, यहीं पर कर लिया जाय ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. Mr. Sanyal, please conclude.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Sir, heat does not pay. What is needed is light. I am prepared to throw light. But they want to remain always in darkness. They will not face light.

SHRl A. D. MANI: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am not at all happy that this and other Ordinances should have been placed before the House and Bills should have been introduced to ratify these Ordinances. Sir, it has been mentioned in the other House that over Rs. 900 crores are yet to be realised as tax arrears, and this has been reported by the Auditor-General himself. Now, if a business concern carries on its affairs in the manner in which the Government is doing, the Managing Director will be sacked. The t thing; that a business concern tries to do is to see to the quick and ?edy realisation of arrears. While so much of arrears are yet to be collected, the Government has brought Bills which are going to yield Rs. 6 or Rs. 7 crores as in the case of ipers and other smaller items. I wonder whether the Government would like to continue the precedent of bringing taxation by Ordinances. Sir, I hope that these are the last Ordinances which have been issued by the Government because taxation should be brought forward as a Bill

before Parliament and Parliament's approval should be sought before it is introduced.

Sir, I would like to concentrate on clauses 3 and 4 of the Ordinance which relate to newspapers, a subject about which, I am sure all Members will agree, I can speak with some knowledge. My hon. friend, Mr. San-yal spoke about newspapers making huge profits. I would like to dispel the impression that newspapers are making huge profits. Even one of the so-called metropolitan papers, published in Delhi-i do not want to mention the name of the paper; it has got an edition in Calcutta—is running into a loss of Rs. 8 lakhs per quarter.

Sir, when this matter of excise duty on newspapers was considered by the Constituent Assembly, it was due to the effort of Mr. T. T. Krishnamachari that this was put on the Central Schedule and not on the State Schedule. Mr. Krishnamachari felt and others agreed with him that this power should not be given to the States but only to the Central Government. And for the first time in the history of India the newspapers are being taxed. On the ground of principle this taxation is open Io grave objection because it is a taxation on knowledge. If you are going to tax newspapers, why not tax books? Books are also printed matter. Now it opens up many theoretical objections regarding, taxation and knowledge. Whether newspapers give knowledge or not, I am not in a position to say now. But I would like to say also, however competent the Ministers may be. however competent the Deputy Finance Minister may be in her subject, Ministers in general do not understand two professions, medical profession and pewspaper profession. These are the two professions which only the practitioners in this profession understand . . .

AN HON. MEMBER: Legal profession also.

SHRI A. D. MANI: In legal profession anyone who has got common-sense can argue. Law is sometimes commonsense. Sometimes law is without sense also. But I would like to say that as far as newspapers profession is concerned, I was a member of the Press Commission, I was Vice-Chairman of the Small Newspapers Committee which conducted extensive inquiries into the conditions of the newspapers industry. The principal fact that the Government should realise is that this is only industry where cost of production is not related to the sale value. Sale value is determined by convention. In Britain it was one penny per paper 25 to 30 years ago. 'The Times' is sold for old six pence. Similarly, in India we have been accustomed to one anna newspapers, two anna newspapers. The cost of production does not count at all in determining the sale value of the newspaper. Unfortunately the cost of production of newspapers has gone up in recent years on account of the rise in the price of newsprint, thanks to devaluation and thanks also to overseas producers of newsprint raising the value of newsprint. NEPA newsprint has recently raised its value by 25 per cent. All that goes into production costs. Now you will be very much surprised to know that 'Hitavada' which you read in Nagpur costs 38 paise per copy but is being sold for 12 paise per copy. But on account of the excise duty the price has changed. Therefore, customs de-termine the value of newspapers and not any other consideration. Mr. Sanyal spoke about huge profits that are being made by newspapers. I would like to tell you as one who was Vice-Chairman of the Small Newspapers Committee that medium newspapers and small newspapers are running into heavy losses because the newspaper industry is a protected industry from the point of view of labour. There is the Working Journalists Act. We are asked to a financial burden which no er establishment or industry is ed to bear. I am not complaining about this burJen. But we are in a very disadvantageous position in re-d to the control of costs. This is er which, must be borne in mind. The honourable Deputy Finance Minister might note that she has levied a 2 paise flat duty on •,'spapers. Now, 2 paise for the 'Times of India' means nothing, But 2

[Shri A. D. Mani] paise for small newspapers of Rajasthan or Kashmir means quite a lot. You must also see the per *capita* income of the people living in those areas.

A man who stays in Delhi does not mind spending 2 np. extra on his newspaper. There are various other considerations in regard to fixing of the excise duty on newspapers. If I had been consulted in the matter—I know government does not consult anybody before taxation measures are announced—I would have told them that if some duty had to be levied, it should be a graded duty and not a flat duty because the burden of 2 np. on a paper which has a circulation of 17,000 is greater than 2 np. for 'The Hindu' or 'The Statesman' or 'The Indian Express'.

The other point I wanted to bring to the notice of the Deputy Finance Minister is that the newspapers have raised their price now and the customers are complaining. In Calcutta there was a newspapers hawkers' strike. Years ago Government brought forward the News Price Page Schedule Order. This was struck down by the Supreme Court in the Sakal case which has been quoted in connection with the 25th Constitution Amendment Bill. The Supreme Court considered it an interference with Art. 19(1)(a) relating to freedom of expression. I would suggest to the Deputy Finance Minister that this is the most appropriate time to enforce the Price Page Schedule Order and with the little influence I have with the newspaper profession, I would ask the newspapers to accept the price page schedule because newspapers are finding it very uneconomic to bring out a large number of pages. Why should government hesitate to bring forward price page schedule now in the existing emergent situation. I would like the hon. Deputy Finance Minister to bring this matter to the notice of the Ministry of Information and Broadcasting. In fact I was talking to some person in regard to this matter. I was told: "If you yourself offer price page schedule, many newspapers will accept it, because they have got to pay this extra duty." The costs are going up and it will te a very good protection to small papers. The recent agitation against the rise in the price of newspapers is against the very spirit of the price page schedule order because what the newspapers have done is because their cost of production has gone up, they have raised the price. I would like to say further that the Deputy Minister of Finance might consider the question of exempting newspapers below 80,000. I am told that as a result of a deputation which waited on the Finance Minister from Maharashtra, the Finance Minister agreed to waive the excise duty in the case of newspapers with a circulation of 15,000. This 15,000 limit was fixed by the Small Newspaper Committee before devaluation. In 1965 we reported and in 1966 there was devaluation. The price of newspaper went up and the Nepa newsprint has gone up still further. There is no point in sticking to 15,000 as the norm for determining a small newspaper. My suggestion, as one who has spent in tne profession for 40 years, would be that the newspaper is not viable or economic unless it has got 30,000 circulation. It is, therefore, better to fix it at 30,000 and exempt newspapers altogether which fall below that category.

The other point that the Deputy Finance Minister should bear in mind is that newspapers are published from various centres. The government is obsessed with the newspapers combine. There is one newspaper in Madhya Pradesh published at these centres—Indore, Raipur, Nagpur, Bhopal and Jabalpur. You know the paper called 'Nav Bharat'. This is not a very big paper. It does not make millions as some people imagine.

Sir, in the case of this newspaper what the Government must do is that the combined circulation must be taken into account. It is extremely unfair in the case of the "Nav Bharat". I know, Sir, i$_n$ the case of this paper, some of the editions are losing. My own paper, with which I have no financial interest at all and in which I have worked always in an honorary capacity for the last 35 years and I have not drawn any salary, is running at a loss. Now, to

raise the price, because you have said 15,000, for both the units, mtans hardship which these small newspapers cannot bear. The suggestion I would like to make to the Ministry is . . .

AN HON. MEMBER: What about your paper?

SHRI A. D. MANI: Mine$_s$ is a medium newspaper according to their definition.

SHRI JAISUKHLAL HATHI (Gujarat): Mani is big!

SHRI A. D. MANI: This Mani is not big. He is a little vocal. My point is . . .

SHRI OM MEHTA: What is the circulation of the "Hitavada"?

SHRI A. D. MANI: It comes to about 16,000 to 18,000. That is all and it would not cross the limit and that is where my suggestion comes. What I am suggesting is that you should take the individual units into consideration. In the cause of the "Nav Bharat" some papers are always above 15,000. Tax them. Why tax the unit which is losing. This is unscientific and cannot be justified. Do not bring in ownership considerations into this matter.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): You are an Editor also.

SHRI A. D. MANI: I am an Editor. But I have been an M.P. for a longer time than you have been as an M.P.

SHRI A. G. KULKARNI: But memtership is different from editorship[1].

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right, please.

SHRI A. D. MANI: Sir, the ether point that I would like to bring in is this: As I said, politicians and the Ministers understand many problems. But I want to repeat the point that they do not understand the newspapers at all and they do not understand the newspapers as much as we do.

Sir now the Minister says, under Clause S of the Bill, "Newspapers and all other periodicals." Then, Sir, the Explanation says something which means "any printed periodical, containing news and comments on news". Sir, there are scientific journals which comment on scientific news. Do you want to put a tax on scientific journals? Sir, there are art journals which comment on items connected with art. There are fashion journals wihch give news and comment on news about the mini-skirt and all other things of this nature and it is also news. Therefore, Sir, I would like the Government to consider the question of exempting all papers which do not fall into the categories of dailies and weeklies, any of the periodicals. There are monthly periodicals, periodicals of stories, short stories. Is it a periodical? There are references also to the current news in them and there are also cartoons about the political figures in the monthly periodicals. Why should the Government try to tax these poor monthlies, the poor fortnightlies, and the poor quarterlies. It is totally unnes-sary for the Government to tax these journals and it means hardship for the management as well as the readers.

Now, Sir, the hon. Minister stated in the other House that she was going to get Rs. 7 crores from this taxation on newspapers and during the current year, during the unexpired portion, she is going to get Rs. 2 crores. Sir, let them stop constructing one building in New Delhi in the Parliament. Street area or somewhere else and they will make that money and, so, Sir, this Rs. 7 crores is a small one.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Only then the scarcity of accommodation will be met.

SHRI A. D. MANI: Sir, Rs. 7 crores means four days'(Ttme *Bell rings.)* money spent on refugee relief. I would,, therefore, like the Minister to consider the suggestion that these dutie; should be continued till only the budget session of Parliament and that she should immediately take steps to see that relief is given . . . *(Time Bell rings.)*

Sir, I am finishing now.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Mr. Mani's suggestion is a very good one.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: There should be a tax on talking also.

SHRI A. D. MANI: What is it?

SHRI AKBAR ALI KHAN: He says that there should be a tax on talking also.

SHRI A. D. MANI: Sir, if such a tax is to be put, it will not fall on me, because whenever I speak, I do not cross the time-limit and I speak to the point. So, Sir, my request is that you should try to avoid fresh duties.

Let us not bother about Rs. 2 crores. Let us have a graded tax. And for Heaven's sake, exempt journals below 30,000 circulation.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति जी, मेरे ऊपर जरूर रहम करेंगे क्योंकि मैंने निरनुमोदन का प्रस्ताव पेश किया था और मुझे खेद है कि मंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव पेश करने के बाद भी अपने बिल के सम्बन्ध में लिखा लिखाया ब्यान पढ़ दिया और इस तरह से उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया ।

श्री ओम मेहता : मंत्री जी ने तो अभी जवाब दिया ही नहीं । वे जवाब अब देंगी । उस समय तो उन्होंने बिल को मूव किया था ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : श्रीमन्, मुझे रिजोल्यूशन पर जवाब देने के लिए कहा गया है । अभी माननीय सदस्य श्री गोरे जी ने बिलकुल उचित बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया कि मेरे द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों का हवाला मंत्री के जवाब में कहीं नहीं आया । जब किसी चीज पर डिबेट हो, किसी रिजोल्यूशन पर बहस हो, तो बहस होने के बाद यह परिपाटी बनाई जानी चाहिये कि जिन मुद्दों को विवाद म उठाया गया हो उनका जवाब दिया जाय । इस परिपाटी पर जरूर विचार किया जाना चाहिये कि अगर किसी स्टैट्युटरी रिजोल्यूशन पर विवाद हो तो सरकारी प्रवक्ता द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर जरूर आना चाहिये तब ही तो मेरे प्रस्ताव को पेश करने का कोई औचित्य हो सकता है । फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री सान्याल जी ने मेरे रिजोल्यूशन के समर्थन में जो बातें कहीं हैं, उसमें जो मुद्दे उ ाये हैं, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं ।

मुझे इस चीज के बारे में व्यक्तिगत जानकारी है । बंगला देश से आये हुए विस्थापितों के लिए हम लोगों को भी शिविर चलाने की इजाजत दी गई थी । कुछ महीनों तक हमने शिविर चलाये और जिला अधिकारियों के साथ मैंने स्वयं बात की थी कि हमारे द्वारा चलाये गये शिविरों के विरुद्ध उनको कोई शिकायत नहीं थी । लेकिन सरकार ने कुछ महीने पहिले यह नीति घोषित कर दी कि गैर सरकारी संगठनों को इन शिविरों को चलाने की इजाजत नहीं दी जायेगी । हम लोगों के हाथों से वे शिविर ले लिये गये और अब उन शिविरों को चलाने के लिए कर्मचारी भर्ती किये गये हैं ।

श्री शीलभद्र याजी : पुराने ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : अगर आप उन्हें पुराने कहते हैं युवा कांग्रेस के दफ्तर के सार्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति हैं अगर यह पुराने पन का कोई प्रमाण है तो श्री याजी मुझे माफ करेंगे । श्री सन्याल जी ने जो आरोप लगाये हैं वह इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस तरह के लोगों को भर्ती किया जा रहा है ।

सरकार ने टैक्स लगाते समय जनता के सहयोग की बात कही थी लेकिन जनता जितना सहयोग कर रही है उस सहयोग के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से प्रशंसा हीं नहीं थीं बल्कि सरकार ने उस जनता द्वारा दिया जा रहा सहयोग को बंद कर दिया । अब वहां पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है । मेरी सूचना है कि करीब 16 हजार लोगों को इन विस्थापितों के शिविरों में काम करने के लिए रिक्रूट किया गया है ।

श्री महावीर त्यागी : ऐसा तो नहीं है कि शरणार्थियों के बीच में से किया गया हो ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : शरणार्थियों में से नहीं किया जा रहा है बल्कि भारतवासियों में से किया जा रहा है । जो संगठन सहायता शिविर, काम कर रहे है उनसे वे शिविर ले लिये गये हैं । इसका परिणाम पीपुल्स पर्टिसिपेशन एसपेक्ट पर प्रतिकूल पड़ता है, ऐसा मेरा कहना है । हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग जबरदस्ती इन शिविरों में घुसें जहां पर सरकार हमको घुसने देना नहीं चाहती है ।

वह तो इस मानवीय सेवा के क्षेत्र में भी वह भेद भाव करना चाहती है । कल ही मैं टोकना चहता था अपने मानवीयसदस्य श्री भूपेश गुप्त जी को जब कि वह रूस के द्वारा भेजी जाने वाली सहायता को उन्हीं के सगठनों के मार्फत वितरण कराने की अनुमति दी जाय इस का बड़े जोर से आग्रह कर रहे थे और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि हम उस को कंसीडर करेंगे तो अगर बाहर से आने वाली सहायता के बारे में महज इस वजह से कि वह बाहर से आ रही है उनकी एक विशेष पार्टी के सगठनों को इजाजत मिले उसको वितरित करने की, इस के लिए अगर दबाव आप पर पड़ सकता है और इससे ज्यादा दबाव देश वासियों के स्वंय के प्रयत्नों से और उनके स्वंय के कांट्रीब्यूशन से जो सहायता शिविरों में मदद करने के प्रयत्न हो रहे हैं उसका वजन बाहर से आने वाली सहायता के मुकाबले में सौ गुना ज्यादा पड़ना चाहिए । इस संदर्भ में इस पर वह पुनर्विचार करें। जैसा कि मैं ने कहा जनता केवल इन टैक्सों के लिए नहीं बंगला देश के इस प्रश्न पर बड़े से बड़ा बलिदान करने को तत्पर है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार जनता के द्वारा दी जाने वाली सहायता, और उस के सहयोग की इज्जत करना चाहती है? क्या सरकार उस को स्वीकार करना चाहती है ? या केवल अपने खजाने में जो कमी आ गयी है उसको पूरा करने के लिए बंगलो देश के नाम का उपयोग करना चहाती है, यह एक सीधा सा आरोप उठता है । इसी आधार पर जो अध्यादेश इस को लागू करने के लिए जारी किया गया मैं फिर से सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ऐसे काम के लिए जारी किये गये अध्यादेश का उन्हें कदापि समर्थन नहीं करना चाहिए ।

SHRIMATI SHUSHILA ROHATGI: Sir, I am extremely sorry if I did not rise up to the expectation of Shri Bhandari in refuting some of the charges that he has levelled, or in clarifying certain things. But I think I did not rise at all, and since I had no *tantric* powers of explaining myself without speaking, I just do not know how I could have intercepted the hon. Member.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: You could have if you wanted to.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: With your consent and with your permission, Sir, I am now going to speak to reply to certain comments.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Then it means that the questions raised by me while moving my Resolution, there were no official comments on them, and, I have replied to my own Resolution without hearing or being given the opportunity to hear any comments from the Government.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: After I have explained, if I do not think that we have much left after that, I think, it was not very fair to have a comment made when one is not given the privilege or the chance to speak.

Anyway, Sir, I am very grateful for the very valuable suggestions that have been made by the various Members, and of course we are not generous. We are not medical men, we are not specialists, as some of our colleagues have said. But the criteria are, I suppose, the same whether we are elected to this side or we are elected to the other side and today, the issue before us is a very important issue and I wish certain issues *I* were not raised today as they have been by certain Members. I think this was an occasion when all the bitterness, which has crept into this occasion today, could have been avoided in fact, should have been

[Shrimati Sushila Rohatgi.]

avoided, and I think some Members have certainly not contributed to the cause of Bangla Desh by having mentioned many a thing, and I am sorry that certain things have been done.

Now, Sir, in so far as the Jana Sangh is concerned, they made a very good case of their cause, but the main attack has been that there was a deliberate attempt on the part of the Government to ignore Parliament and to have brought the Ordinances to take effect on and from that particular day. I think, Sir, I have explained that thing in detail yesterday, and I would not like to dwell on it again, and I would appeal to Mr. Bhandari and through him to the other colleagues that there was no intention on the part of the Government to treat the House with any contempt whatsoever. That question does not arise, and if there is any fear or any apprehension, we would like to clarify the position, as we did the other day, today also. As I said earlier, it was a coincidence that the date has clashed. Otherwise, there was nothing wrong with us. Now, apart from that there is a great difficulty when we levy a tax of the type that we levied yesterday, that is, the railway fares. We are accused of hurting the feelings of the common man.

Today when we levy a tax on inland air travel we are accused again of hurting the other element. 1 do not know how far, in which way to accommodate everyone there because either it is the poor man's bogey which comes into it or, if not the poor man's bogey—and it is a far-fetched imagination—there are sympathisers even for those people who pay for air travel. So for every action of the Government it is accused on some ground or other.

About the notification, I think it has been there before everyone. It is a notification of the 5th November where an Explanation has been given for all the things which have been exempted. It is very very categorical and I do not know why people should have any doubt.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: This notification is in pursuance of the Ordinance that was issued which means once the Ordinance lapses this notification also goes.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: This notification which was issued on the 5th November exempts certain newspapers and periodicals. That has been very very clear. It is issued under rule 8(1) of the Central Excise Rules. For your clarification that point also is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Would that notification have the force of law?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Of course. Sir. The rule-making power is there.

Now, the main point which has really troubled me and which I would like to argue with my friends is about the definition of "visthapit". Mr. Bhandari, I am sorry there is one point which you had mentioned —that you would like the word "visthapit" to be there. I fail to understand how a senior Member like Mr. Bhandari could have thought that there can be any other "visthapit" in the country than those who are affected by this tragedy.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : You have not used the word "visthapit"; you have used the word "sharnarthi" and that there are so many "sharnartbis" here.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: In the present context can we think of any other "saranarthi"? Is not the entire atmosphere of the world re verberating with the tragedy that has happened there? Can we think cf any other "saranarthi" just now except the Bangla Desh "saranarthis?" I think it is undermining the importance and the magnitude of the tragi hich has been perpetrated there. I do not think he really means that when he used the word and I v Ii him not to give l"" much al i to the argument that is stated here. That might have been a political argument.

The other point is mentioned bv our friend, Mr. Sanyal of the CPM, who is a very senior Member. He said that the young people, educated people are grudging paying this two paise excise which is being levied on the newspapers. I think he has under-rated and under-estimated the patriotism and the goodness of our young people today. I do not think any man, old or young—especially the younger people—would object to this levy of two paise. I think it is doubting their patriotism, something which even our friends in the CPM would not have meant whatever may have been the words used. All I may say today is that there is an involvement of the public as a whole in a good cause and for getting a sizeable sum of money through the mass media—-for a good cause— and without much of administrative difficulties in a matter in which all the people wanted to contribute irrespective of party affiliations. I thought this is the charge and I would not like to substantiate it.

About Mr. Mani, he is a very good journalist and he has made certain very good suggestions, especially about the Price Order. I will pass them on to the Information Ministry which is directly concerned with it and they will consider the matter whether it really deserves justification under the arguments made there.

About the Jana Sangh, the main charge they have levelled against us is that we procrastinated, that we delayed, that v/e did not give our decision at that time and, therefore, the entire bungling was due to the Government's incoit-ect policy, That is the incorrect policy.

Sir, we do not have to look back very far. We have to look back to the performance of the Jan Sangh. Whenever and wherever they have got an occasion to be in any Ministry-making in a State—there have not been many Sta[e]e> . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Is this the proof?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: We know in our State of Uttar Pradesh . . .

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: You may beat about any tush. This is beating about the bush.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: We judge according to the performance and based on the past performance of the Jan Sangh Party, we are not in a position to accept what they dictate and. therefore, we think the world has come to realisation to vindicate the stand that has been taken by the Government on this issue of Bangla Desh.

Coming to certain other things concerned with this Bill, Sir, we know there were certain administrative difficulties. About 70 crores of stamps had to be printed in the Security Press. They needed sometime and the machinery they have could not be used together, exclusively for printing these stamps alone. They were stamps of various denominations, of various kinds. Another shift has been introduced. We knew that it required some time and, therefore, from that point of view, it was necessary not to cause inconvenience to the public. If adequate number of stamps were not available, the public would have been put to a lot of inconvenience so far as disbursement of the money and other things were concerned.

About the newspaper, the main thing that can be said, that was motivated by the reason that they had to get familiarity with the excise formalities including the self-removal procedure and that necessitated some time. If the newspapers were published and they could not be circulated because of the completion of these formalities, a lot of inconvenience to the extent of paralysing the industry would have been there. These were the reasons why it had to be instituted.

I would only like to say that because of this, as far as newspapers are concerned, it would be correct to say that nearly 75 per cent of the 'spacers would fall under the exited category. The figure of 90 to 95 is the aggregate percentage both for periodicals and newspapers. If periodicals alone are taken, then 96 per cent of them would come under

[Shrimati Sushila Rohatgi.] the exempted category of having a circulation of less than 50,000. All these figures are with reference to the number of newspapers and periodicals. Thus 75 per cent would be in the exempted category and the balance 25 per cent would fall in the duty-paying category. That too I can divide, if the House is interested, but I would not like to take the time of the House. I have more details, but now I will speak on one more point.

Taking the 1969 figures, the circulation of medium and big newspapers on an aggregate is 6.2 million approximately per day aggregate out of the total of 7.8 million per day. In other words, 80 per cent of the circulation was accounted for by the big and medium newspapers. The same is about the periodicals and I think that meets the arguments of the Members.

I would only say that much in reply to all the points have been asked. As we stand united on the Bangla Desh issue, I only wish that we will get the united support that we deserve.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House disapproves the Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance, 1971 (No. 16 of 1971) promulgated by the President on the 22nd October, 1971."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Stamp Act, 1899, the Central Excises and Salt Act, 1944 and Excise and the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1 *(Short Title and Commencement)*

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : Sir, I move—

"That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the stamp and Excise Duties (Amendment) Bill, 1971, as passed by the Lok Sabha namely: —

'That at page 1, lines 5 and 6 be deleted.' ."

The question was proposed.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : बिल की धारा 2 से 5 तक जिन्हें अभी हम पास कर चुके है इसमें इस बात की व्यवस्था है कि जो अध्यादेश जारी किया गया था वह इस कानून के लागू होने की तिथि तक जारी रहेगा और जिस दिन वह अध्यादेश समाप्त होगा उस दिन से उसी क्षण से यह कानून लागू हो जायेगा। श्रीमन् मेरा यह संशोधन है कि कालम एक की (दो) में "यह नवम्बर 15, 1971 को प्रवृत हुआ समझा जायेगा" इसको यहां से विलोपित किया जाये।

श्रीमन् अगर यह विलोपित नहीं किया गया तो 15 नवम्बर 1971 से लेकर जिस दिन यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सहित स्टेट्यूट बुक के लिए आता है, एक ही मतलब के लिए दो कानून देश में रह जायेंगें यह कानून भी 15 नवम्बर 1971 से लागू हो जायेगा और अध्यादेश भी 15 नवम्बर से लेकर जब तक उस नये कानून पर दस्तखत नहीं होते तब तक लागू रहेगा। वैलीडेटिंग क्लाज 5 में अध्यादेश के अन्तर्गत जारी की गई सब सूचनाएं और अध्यादेश के अन्तर्गत किये गए सब काम और अधिकार वह इस नये कानून के अन्तर्गत वाजिब मान लिये गये हैं। इस लिए 15 नवम्बर से लेकर परसों तक भी अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो 4 दिसम्बर तक स्टैम्प ड्यूटी और उत्पादन शुल्क के संबन्ध में, एक ही काम के लिए दो कानून स्टेट्यूट बुक में रहेंगें। यह एक लीगल एबसर्डिटी होगी ।

इस बात को ध्यान में रखकर हमने इसकी धारा 5 के पहिले खंड में यह स्वीकार किया है कि इस कानून के लागू होते ही अध्यादेश समाप्त हो जायेगा और अध्यादेश के समाप्त होते ही यह कानून लागू हो जायेगा। तो इस तरह से एक पल के लिए

भी बीच में गैप नहीं है । इस तरह से दोनों कानून एक ही समय लागू रहने का हम एक मौका काम न करें इस धारा के बिना साधारण विधान में यह व्यवस्था रहती है कि जब कानून बनता है तो उसको लागू करने की कोई तारीख नहीं रहती क्योंकि बहुत से कानून ऐसे बनते हैं जिनमें इस बात का विधान होता है कि यह कानून उस दिन से लागू हो गा जिस दिन से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा तब तो इसमें गैप का सवाल खड़ा हो जाता है लेकिन अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मतलब यह समझा जा सकता है कि जिस समय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस कानून में हुए अध्यादेश समाप्त हो गया उस व्यवस्था के अन्तर्गत कानून लागू हो जायेगा । इस कानून के पास किये जाने के कारण कोई गैप नहीं है । किसी चीज को जिस को हम आज तक कर चुके हैं, उसे गैर कानूनी साबित करने की बात नहीं है ।

मुझे इस बात का खेद है कि हमारे तर्कों का जवाब नहीं दिया गया बल्कि जन संघ के नाम पर उन तर्कों को एक तरफ फेंक देने की कोशिश की गई अगर मैं जन संघ सदस्य के नाते यह सुझाव दे रहा हूं और आप उसको मानना नहीं चाहते हैं, तब मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है लेकिन हमें तो एक लेजिस्लेटिव प्रोपोजिशन के बारे में विचार करना है कि दो कानून एक ही समय पर जारी न रहें एक ही बात के लिए हमें सावधानी बरतनी है कि इसमें सब क्लाज 2 है वह ओमिट होना चाहिये और यही मेरा संशोधन है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I would like to draw the attention of the hon. Member to clause 5 (1) of the Bill which repeals the Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance, 1971.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : From what time?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: The moment the Bill is passed, the Ordinance will be repealed. The point that you have raised is Ii very relevant one and for your information I have given that. Another point hon. Member has mentioned is that it should be levied after it has received the President's absent. The only reason why the Ordinance was ulgated was the urgency behind it. Every day's delay causes a substantial loss of revenue.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: I am not objecting to it.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: We have approved the Ordinance just a minute before.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Now, the Ordinance having been approved by Parliament, it stands on the Statute Book. Two Acts simultaneously remain on the Statute Book from the 15th November till 4th December.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: I have already replied to that point. We cannot accept the amendment.

SHRI AKBAR ALI KHAN: May I just submit that the moment this law comes into force, it will be in operation? Till then, whatever provisions were there would remain. After the passing of this Bill, the Ordinance does not stand at all. Where is the question of two laws prevailing at one and the same time?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : My objection stands even after the explanation. Whatever you decide, you can, I leave it to the brute majority.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing it?

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: No, Sir. I stand on very solid grounds.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"1 That the Rajya Sabha recommends to the Lok Sabha that the following amendment be made in the Stamp and Excise Duties (Amendment) Bill, 1971, as passed by the Lok Sabha namely: —

'That at nage 1, lines 5 and 6 be deleted'."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was adopted. Clause 1 *was* added to *the Bill. The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The Question was proposed.

श्री शील भद्रयाजी : माननीय डिप्टी चेयरमन महोदय, मुझे खुशी है कि इतना विरोध करने पर भी सब लोग इस का समर्थन कर रहे हैं लेकिन श्री शशांक शेखर सान्याल ने कुछ ऐसी बातें उठायी हैं कि जिन के लिए मुझे बोलना पड़ा है हम लोग जो रिहैबिलिटेशन कंसल्टेटिव कमेटी है उस के सदस्य होने के नाते जो बंगाल के रिफ्यूजी कैंप्स हैं उन को देखने गये थे और वहां किस तरह से डिस्ट्रिब्यूशन होता है, राशन कैसे बंटता है, वगैरह उन तमाम चीजों को हमने देखा है। उनके अभियोग बिल्कुल गलत, असत्य और बेबुनियाद है। राजनैतिक पार्टियों और खास कर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया उन को भी विदित है जैसा कि भंडारी जी ने इस को स्वीकार किया कि उनकी पार्टी के लोग भी उसमें मदद देते थे लेकिन जो कार्ड का डिस्ट्रिब्यूशन होता है या राशन का डिस्ट्रिब्यूशन होता है उसे कोई कार्यकर्ता नहीं करता उसे सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो सरकारी कर्मचारी हैं और नार्थ बंगाल में खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वेही करते हैं अब उन्होंने चार्ज लगाया कि जो रिक्रूटमेंट होता है उस में कांग्रेस के वर्कर्स को ही रख लिया जाता है मैं उनको बताना चहता हूं कि उस के लिए एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है उस में उन का सेलेक्शन होता है और उसमें कांग्रेस की या किसी और पार्टी की बात नहीं होती है उस रिफ़्यूजी कैंप को देखने के बाद जो गड़बड़ी वहां होती थी उस के 23 प्वांइट हम लोगों ने लिख कर वहां के जो गवर्नर हैं चूंकि वही सब के अधिकारी हैं उन को और रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर को दिये थे लेकिन यह बात बिलकुल बेबुनियाद है पाकिस्तान के एजेंटों की तरह कहना कि पोलिटिकल पार्टीज इस तरह की बातें करती है और ऐसा कहना उन को शोभा नहीं देता।

दूसरी एक और बात उठायी गयी, हमारे श्री भंडारी जी ने कहा कि अभी तक सरकार की ओर से बंगला देश कि सरकार को, स्वीकृति देने, मान्यता देने की बात स्वीकार नहीं की गयी, अभी तक उन को जवाब भी कभी नहीं मिला।

जवाब में उनको एक सेंटेंस मैं देता हूं। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने जब आजाद हिन्द गवर्नमेंट बनाई, तीन लाख की फौज बनाई तो किसी ने हमारी गवर्नमेंट को रिकगनिशन नहीं दिया जब तक कि उसे कोई भूभाग नहीं मिले और इसलिये अंडमान और निकोबार जो कि हमारा भूभाग था, ब्रिटिश इंडिया का भूभाग था, उसको जब जापानियों ने उनको आफर किया तब उसके बाद फिर सरकारों ने आजाद हिन्द गवर्नमेंट को मान्यता प्रदान की। अभी तक जो हमारे मुक्तिवाहिनी के लोग लड़ रहे थे उनके पास भूभाग नहीं के समान था, अब काफी भूभाग करीब 54 हजार वर्गमील, स्क्वेयर-माइल्स, आ गया है। अब यह क्वेश्चन आफ डेज ही रह गया है कि मान्यता कब मिलती है इसलिये अधीर नहीं होना चाहिये। चूंकि उन्होंने जवाब मांगा था कि सरकार के पास क्या जवाब है इसलिये थोड़े में जवाब दिया। उनको थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिये। जय हिन्द। जय बंगला देश।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति जी, मुझे खेद है कि सरकारी प्रवक्ता के रूप में याजी जी से ही पाला पड़ता है, अन्य सभी सरकारी प्रवक्ता ऐसे विवाद के प्रश्नों पर मौन धारण कर के अपनी असफलता स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं। आज याजी जी ने कहा कि 54 हजार वर्ग मील उनके कब्जे में जमीन है, अब तक जमीन नहीं थी इसी वजह से मान्यता का सवाल हल नहीं हुआ था। बेहतर होता कि सरकारी बैंचों की तरफ से यह बात सामने आती।

श्री शील भद्र याजी: मैं तो सरकारी बैंच में हूं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : ट्रेजरी बैंचेज, आफिशियल बैंचेज नहीं । अभी तक जितने विवाद हुये हैं और जब जब इस बात का उल्लेख किया गया भूमि होना या न होना इसका आज तक कभी भी सरकार की तरफ से तर्क नहीं दिया गया है ।

श्री ओम् मेहता : बताया गया है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : अगर पार्लियामेंटरी अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से इस बात को कह रहे हों तो मुझे इसको स्वीकार करना पड़ेगा लेकिन वह अपनी सरकार की स्थिति को और अधिक जटिल न बनाये इसलिये इस बात को जरा अपने रिकार्ड्स में देख कर और अपनी सरकार से पूछ कर फिर इस सदन में स्टेटमेंट दें ।

श्री ओम् मेहता: मैं तो कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपने दिया तो है ।

श्री ओम् मेहता : मैंने कुछ नहीं दिया ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : आपने कहा है ।

श्री ओम् मेहता : क्या कहा ! जरा बताइये तो ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : यह तो कहा गया कि जमीन नहीं है इसलिये सरकार को. . . .

श्री ओम् मेहता : मैंने कहा कि जो हमारी पालिसी थी उसके बारे में कई बार प्राइम मिनिस्टर बोल चुकी हैं यहां ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : मुझे खुशी है कि आपने अपने-आप को करेक्ट कर लिया ।

श्री ओम् मेहता : करेक्ट करने की कोई बात नहीं ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : इतना निश्चित है कि मेरे तर्क का जवाब मिनिस्टर कंसर्न्ड भी नहीं दे सकीं । इसके बारे में जनसंघ ने संविद सरकारों में क्या किया क्या नहीं किया यह डिसकशन का सबजेक्ट अगर होगा तो उसका भी मैं जवाब दूंगा । मैंने यह तर्क दिया था कि पिछले सात महीनों से सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी लेने के बाद भी कि हम उपयुक्त समय पर इसको मान्यता दे देंगे और क्योंकि अभी तक फैसला नहीं हुआ है तो क्या यह बात सच है—मैं फिर दुहराना चाहता हूं—कि जो बंगला देश के विस्थापितों की संख्या इस हद तक बढ़ी या इन विस्थापितों के बढ़ने के कारण जिस तरीके पर यह बिल लाने का प्रयत्न किया गया इस परिस्थिति पर निश्चित रूप से सुधार की तरफ अन्तर पड़ता अगर यह फैसला आज से काफी समय पहले ले लिया जाता और सरकार भी बंगला देश. . .

श्री ओम् मेहता : राय का मामला है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : . . . केसाथ भागीदार बन कर बंगला देश के नरसंहार को रुकवाने में और बंगला देश के विस्थापितों के जाने के मार्ग में, व्यवस्था में, मददगार बनती । मैं समझता हूं कि यहां पर केवल जनसंघ ने संविद ने क्या किया और क्या नहीं किया यह तर्क उसी तोर पर फिर से दुहराया जा सकता है लेकिन यह इस सवाल का जवाब नहीं होता । आज भी देश को इस कठिन परिस्थिति का, इस बढ़े हुए खतरे का, सामना करने की नौबत न आती अगर इस बीमारी की प्रारम्भिक अवस्था में, उस छोटी फुंसी का इलाज कर दिया जाता, जो कि आज एक फोड़ा या नासूर की शकल लेने की उसकी अवस्था बन गई है । जिसके लिये केवल इसी टैक्सेशन मेजर को नहीं बल्कि पता नहीं इस देश को आर्थिक दृष्टि से भी कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों के लिये मजबूर हो कर स्वीकृति देनी पड़ेगी ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार भविष्य के लिए जब ऐसे टैक्सेशन मेजर्स लाने के लिए पार्लियामेंट के सामने उपस्थित हो तो नीति संबंधी जो उसकी पृष्ठ भूमियां ह, उनके संबंध में पूरी जानकारी रखे । अगर सरकार अपनी

जिम्मेदारियां समझ कर उचित समय पर उचित निर्णय लिया करे तो इस देश को आने वाले इस बहुत बड़े आर्थिक कठिनाईयों के बोझ से बचने में मदद मिलेगी । धन्यवाद ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार की तरफ से मुझे केवल यही कहना है कि यह जो बंगला देश की समस्या है इसको फुंसी का रूप समझकर सरकार ने कभी नहीं देखा है । यह शुरु से ही फोड़े से बड़ी चीज थी । अगर छोटी सी फुंसी होती तो इतनी आसानी से इतनी संख्या में लोग अपना घर-बार छोड़कर वहां से नहीं आते ।

दूसरी बात का जहां तक संबंध है, सरकार की समझ में अभी निश्चित रूप से वह उपयुक्त समय नहीं आया है कि अभी बंगला देश को मान्यता दे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

THE FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL, 1971

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT/ **औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री** (SHRI GHANSHYAM OZA): Sir, I beg to move.

"That the Bill further to amend the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI A. D. MANI) in the Chair]

Sir, the House must have seen that the Bill which I have moved for consideration comprises only of three clauses. Clauses 1 and 3 are absolutely of a formal character. It is only clause 2 which is material for our consideration. This clause only intends to amend the definition as contained in section 2(c) and section 2(i) of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. This is the only purpose of this present Bill. The very fact that we had to promulgate an ordinance to bring into effect this amendment shows how important it is from our point of view.

Sir, under the Constitution the citizens may have a right to practice any trade, profession or business. But the State can put reasonable restrictions in the larger interest of the community. In the case of forward trade we cannot allow citizens to practice forward trade as and in the manner they like. And, therefore, why in the larger interest of the community we have brought forward this Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill.

Sir, we are of the view, as I said in the beginning, that we have to take care of the community as a whole particularly the producers and the consumers. We cannot allow forward trade to have free hand in so far as certain commodities, particularly, the consumer commodities are concerned. We have to take care to see that this sort of trade is not resorted to for raising prices or in any way affecting the interest of either the producer at the one end or the consumers at the other. At the same time, as the House is very well aware, ready delivery contracts are outside the purview of this Bill. It is not necessary to regulate ready delivery contracts in case of citizens who enter into a deal for their consumption. While trying to regulate the forward trade we sometimes have to put bans on certain types of forward trades on certain commodities. We have sometimes to suspend them and we have only cases to regulate them in the larger interest. While doing so, it has come to the notice of the Government that some speculative interest take advantage of the definition of ready delivery contract as it stands today. Under the present definition of the ready delivery contracts, the contract is of a ready delivery nature if within a space of 11 days the parties deliver the goods and pay the price thereof. This definition was taken advantage of by the speculative interest this way.